अब सूखे व अकाल पर हुई अल्पकालिक चर्चा पर ग्रामीण विकास मंत्री जी उत्तर देंगे । .....(व्यवधान).....

DR. (MS.) P. SELVIE DAS (Nominated): Sir, my name is there in the list.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I called your name. But you were not there.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: My name is there in the list.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Your name is very much there. But when I called your name, you were not there.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: Kindly give me an opportunity to speak.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI SURESH PACHOURI): I have called the Minister.

SHORT DURATION DISCUSSION

Drought and famine conditions in various parts of country, particularly in Gujarat and Rajasthan - Contd.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सूखे पर हुई बहस में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और जिस ज्वलंत समस्या से आज हम जूझ रहे हैं, उस पर हमारा मार्गदर्शन किया ।

श्रीमन्, एक विपत्ति के घावों को सहला कर हम उससे उबरे भी नहीं थे, उड़ीसा की और दूसरी विपत्ति ने हमें आ घेरा । यह जो विपत्ति है, यह किसी की बुलाई हुई नहीं है, किसी की लगाई गई नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है बल्कि प्रकृति के प्रकोप ने हमें इस विपत्ति में डाला है और इसकी आवश्यकता है कि बाकी सब बातों से नज़र हटा कर, बाकी सब बातों को दरगुज़र करके सारा देश, सभी राजनीतिक पार्टियां और इस सदन के सभी माननीय सदस्य एक मत से, एक आवाज़ से इस विपत्ति का सामना करें । यह वक्त की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है और समय की पुकार है ।

महोदय, जिन राज्यों में सूखे की समस्या है, मैंने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से

निरंतर सम्पर्क बना रखा है । परसों लोक सभा में बहस होनी थी । परसों सवेरे मैंने फोन करके राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की और उनसे अद्यतन जानकारी प्राप्त की । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से भी मेरी चर्चा हुई । जैसा कि आप जानते हैं कि उनसे तो मेरी चर्चा निरंतर होती रहती है। मुझे उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई वह संक्षेप में इस प्रकार है:

गुजरात के 17 जिलों में 135 तालुका के 9,421 गांव चपेट में हैं। 80 शहर और 4 महानगर भी उससे प्रभावित हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में पानी की विशेष समस्या है, संकट है। अहमदाबाद और गांधी नगर में पहली बार जल संकट है। गुजरात सरकार ने पेय जल की कमी वाले स्थानों पर सौ मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराए जाने का प्रबन्ध किया है। अन्य राज्यों से चारे के आयात की व्यवस्था उन्होंने की है। 157 जल समूह योजनाओं में 70 जल समूह योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। केन्द्र के वाटर टैंकर के प्रस्ताव का मुख्य मंत्री ने स्वागत किया है। रेलवे से जल टैंकर भेजने की तत्काल आवश्यकता नहीं बताई गई है। यदि आवश्यकता हुई तो इसके लिए चार-चार स्थानों पर तैयारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा पांच करोड़ किलो चारे का वितरण किया गया है और राज्य सरकारों ने आठ करोड़ किलो चारे की आवश्यकता बताई है। इससे भी कुछ सघन प्रयास मैंने किए हैं। मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से गुजरात और राजस्थान चारा भेजने का अनुरोध किया है तथा इसके पॉजिटिव रेस्पांस हैं। मैं पंजाब के किसानों को विशेषरूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुतांश में वहां हार्वेस्टर द्वारा कटाई होती है और भूसा व्यर्थ खेतों में बिखर जाता है, इस बार बड़ी संख्या में मैनुअल लेबर के द्वारा पंजाब में गेहूं की कटाई हुई है। वहां पर काफी मात्रा में चारा, भूसा उपलब्ध है और राहत कार्य प्रारम्भ है। आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अनुरूप बीस किलो अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध करावाया जा रहा है। गेहूं का पर्याप्त स्टाक है, ऐसी गुजरात सरकार की सूचना है। राजस्थान के 26 जिलों के 23,406 गावों में अभाव की स्थिति है। राज्य सरकार ने 30 सितम्बर तक राजस्व वसूली स्थगित कर दी है। 16 मार्च से अल्पकालिक ऋण मध्य कालिक ऋण में परिवर्तित किया गया है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति कार्य कर रही है। पचास हजार से ज्यादा पशुओं की देखभाल गौशालाओं के माध्यम से हो रही है। जून माह तक एक लाख पशुओं के लिए गौशालाओं में शरण की व्यवस्था की गई है। चार लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जा रहा है और मजदूरी 44 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। चारा डिपो संचालित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया गया है। पंजाब,

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी चारे, भूसे के आयात की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार से मैंने स्वयं इसके लिए आग्रह किया है। एक ट्रेन जोधपुर और बाडमेर जिलों के लिए भेजी गई है, यह परसों का समाचार है। आन्ध्र प्रदेश में भी 18 जिलों के 17,400 गांव अभाव की स्थिति में हैं और वहां के प्रयासों का विवरण मुझे राज्य सरकार द्वारा मिला है। महोदय, परसों के समाचारपत्रों में छपा था कि राजस्थान और गुजरात से बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन हो रहा है। मैंने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से तत्काल चर्चा की और परसों उन्होंने मुझे फैक्स पर सूचित किया है कि राजस्थान से अकाल के कारण रोजगार की तालाश में लोगों का पलायन नहीं हुआ है । यह मुख्य मंत्री का परसों का संदेश है । गुजरात का कहना है कि Newspaper extracts mention that there is a large scale migration from Gujarat because of drought. This is not based on fact; there is no migration due to drought. राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का कथन है जो 'पायनियर' में 26 तारीख को उनके फोटो सहित छपा है It is not as bad as the media says.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : वह राजस्थान के मुख्य मंत्री का नहीं होगा ऑफिशियल्स का है, लाइन पढ़ दीजिए । फोटो उनका है लेकिन आप न्यूज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऑफिशियल्स है ।

SHRI C. P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Newspapers should not be read out by any Minister. He should give his own opinion.

SHRI SUNDER LAL PATWA: No, I am showing, I am not.....गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है और हमारा जो सूचना प्राप्त करने का माध्यम है वह हमारा स्वयं का प्रबंध नहीं है । हम जिस माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं वह राज्य की सरकार है, राज्य का तंत्र है, हमारे देश का संविधान है । उसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं । केंद्र और राज्य की मर्यादाएं उसमें निर्धारित हैं। उपसभाध्यक्ष जी, राजस्थान के मुख्य मंत्री और मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, उन्होंने मुझे 25 अप्रैल,कल की तारीख में पत्र लिखा है, "पिछले दिनों आप से हुए पत्राचार तथा विचार-विमर्श के दौरान राजस्थान में अभाव की स्थिति की जो समझ आपने दर्शाई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा" ...(व्यवधान) अभी मैं खड़ा हुआ हूं । अभी मुझे खड़े हुए तीन मिनट हुए हैं । एक विकराल समस्या हमारे सामने है । आप अभी वहां बैठे हैं । आपको कोट करना है कि नहीं करना है मुझे पता नहीं है । बाल कवि बैरागी जी बैठे हैं । बड़ी जोर से उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की । श्री ब्रह्मकुमार जी भी यहां बैठे हैं । क्या हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का समय इस समय खोज रहे हैं ? आखिर यह समस्या,

अकाल की विभीषिका क्या राजस्थान में पहली बार इतनी प्रबल हुई है । बाड़मेर और जैसलमेर, जिस जैसलमेर से मेरे पूर्वज आए, तीन इंच पानी की बरसात में हजारों साल से वहां लोग जिंदा हैं, हजारों पशु जिंदा हैं । आखिर वे कैसे जिंदा रहे ? वाटर हार्वेस्टिंग का उनका क्या प्रबंध था ? वे बारह महीने कैसे पीने का पानी निकाल पाते थे ? हमने उन पुराने उपायों पर अवलंबन छोड़ दिया । जंगल काटे, चरागाह बर्बाद किए । मैं ज्यादा लंबे विस्तार में नहीं जाऊंगा परंतु यह एक दीर्घकालीन समस्या है जिसमें मानव का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारा योगदान है । मैं आरोप नहीं लगाना चाहता कि उस समय कौन-सी पार्टी की सरकार थी । आखिर अपराध किया है तो हम सबने मिलकर किया है और सजा भोगनी है तो हम सब को मिलकर भोगनी है । अगर उसका सुधार करना है तो हम सब को मिलकर करना है । एक दूसरे के मत्थे पर ढोलकर हम अकाल की विभीषिका को कम नहीं कर सकते । यह जो समस्या है, जो विभीषिका है इसका हमें तत्काल सामना करना है । यह कुल जमा दो महीने या ढाई महीने की तात्कालिक समस्या है । इसका सामना हम कैसे करें यह हमें सोचना है । हमें इसका तत्काल उपाय करना है और हमेशा के लिए इस समस्या से कैसे मुक्ति पाई जा सके इसको देखना है और इसके लिए दीर्घकालिक उपाय भी सोचने हैं । यहां इस पर चर्चा हुई। । क्या हमारे देश में पानी की कमी है ? नहीं है । जितनी मात्रा में हमारी पूरी आबादी को पानी चाहिए उससे अधिक पानी हमारे पास प्रति वर्ष कुदरत देती है, अवेलेबल है, नदियां हैं और प्रचुर मात्रा में पानी है । लेकिन हम प्यासे हैं । यह एक विरोधाभास है । इन पचास वर्षों में हम पानी की उचित व्यवस्था करके उसका सदुपयोग नहीं कर पाए और आज यह समस्या हमारे सामने जिंदा खड़ी है । इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा । तत्काल जो हम कर सकते हैं, राज्य सरकारें कर सकती हैं या मिलकर कर सकते हैं उसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा । मैं एक एक करके राज्य सरकार पर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता, ढोना नहीं चाहता । लेकिन यह जिम्मेदारी उन की है हमारी तो सहायक भूमिका है । क्रियान्वयन उनके जिम्मे हैं, आफ्टरआल इट इज स्टेट सबजक्ट । सेंट्रल गवर्नमेंट या पटवा चाहे भी तो हम जाकर वहां एक्जीक्यूशन नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते । हम सहयोगी की, सहायक की भूमिका में हैं । श्रीमन् मैं केंद्र सरकार की ओर से और स्वयं अपने विभाग की ओर से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिना किसी रंगीन चश्मे के, चाहे वह राजस्थान की सरकार हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे आंध्र की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे किसी भी प्रदेश की हो सब प्रदेशों में हम इस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं । इस बारे में कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के माननीय नेता उपस्थित थे । वहां भी इस पर चर्चा हुई ।

श्रीमन्, सूखा और अकाल, इसमें दो प्रकार की सहायता केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है । एक तो स्कीम है प्राकृतिक आपदाओं पर राहत धन को केंद्र से प्रदाय करने की व्यवस्था, आपदा राशि सहायता कोष । वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 6304 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान पांच वर्ष के लिए किया गया था । उसमें प्रत्येक राज्य का अनुपात निश्चित है । बिरल गंभीरता की जो आपदायें हैं उनके लिए वित्त आयोग ने एक अलग व्यवस्था की है । इन दोनों सहायता कोषों के माध्यम से केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है । दोनों राजकोषों के अन्दर 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र के द्वारा किया जाता है और 25 प्रतिशत अंशदान ...**(व्यवधान)**

श्री अहमद पटेल (गुजरात) : मेरे ख्याल से जिस तरह से उत्तर आना चाहिये, वह नहीं आ रहा है । यह तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पोस्ट आफिस की तरह से काम नहीं कर सकती है । नम्बर दो, स्टेट गवर्नमेंट की जो कमियां हैं, जिनका जिक्र किया गया है, उन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? तीसरी चीज़, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को जो सहायता करने जा रही है, 6 हजार करोड़ रुपये से पांच सालों में क्या होगा, पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे । जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है कि संकट बहुत बड़ा है और इस संकट का मुकाबला करने के लिए वहां की राज्य सरकारों में कुछ कमियां हैं । केन्द्र सरकार उसके लिए क्या कर रही है ? राज्य सरकारें सक्षम हैं या नहीं हैं और जो अभी वहां व्यवस्था है, उसके बारे में आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं । इन सारी चीज़ों का जवाब आना चाहिये ।

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन्, मैंने कई घंटों तक बहस सुनी, यह कुछ मिनट मेरा कथन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । यह वरिष्ठ सदस्य हैं । **(व्यवधान)** आपको सभी कुछ मालूम है तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है क्या ? **(व्यवधान)**

श्री राजू परमार (गुजरात) : जो बताया है, वह मालूम है । वह सब हम जानते हैं कि इतने गांव अफेक्टेड हैं । **(व्यवधान)**

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): This is not the way a Minister speaks. He is a senior Minister and he was the Chief Minister of a State. *(Interruptions)* The hon. Minister should come out with specific answers.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप उनका पूरा उत्तर तो सुनिये । **(व्यवधान)**

श्री रामचन्द्र खूंटिया (उड़ीसा) : जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर तो आना

चाहिये । ..(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : उनका उत्तर पूरा तो होने दीजिये।..(**व्यवधान**)

SHRI RAJU PARMAR: A number of queries were raised by Members. *(Interruptions)*जो क्वेरीज़ हैं, उनका उत्तर तो आना चाहिये ।..(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : हो सकता है आपकी क्वेरी का जवाब थोड़े समय के बाद मिल जाए ।..(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल) : अगर सवाल पूछा जाएगा तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिये । ..(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप पहले पूरा उत्तर सुन लीजिये और अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो बाद में पूछ लीजिये।..(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु : यह सदन की मर्यादा है, बहुत वरिष्ठ राज नेता हैं यह सदन के लिए सही नहीं है।..(**व्यवधान**)

श्री सुंदर लाल पटवा : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने क्या किया, माननीय सदस्यों को यह जानने की ज्यादा बेचैनी है, वह हम पहले बता देते हैं । 1999-2000 में आपदा राहत कोष से राजस्थान को 155 करोड़ रुपये, गुजरात को 121 करोड़ रुपये, आन्ध्र प्रदेश को 107 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 44 करोड़ रुपये जो नियमित अंश बनता था, वह हमने पूरा का पूरा जारी किया । राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, एन0एफ0सी0आर0 का जिक्र करूं, जिस समय इसका गठन हुआ उस समय इसमें 700 करोड़ रुपये का प्रबंध था । 700 करोड़ रुपया दो वर्ष में एग्ज़ास्ट हो गया। आवश्यकतानुसार उसमें 120 करोड़ रुपये की और वृद्धि की गई । उसके बाद कोई वृद्धि नहीं हुई । परन्तु उसमें उस कोष में एक पैसा भी नहीं होते हुए उसी कोष में से 1291 करोड़ इस सरकार ने विभिन्न प्रदेशों को राहत दी है, पैसा भेजा है। इस राहत कोष में चार साल में 1264 करोड़ की राहत दी गयी और 6 महीने में, इस सरकार, मौजूदा सरकार के आने के 6 महीने के बाद 1291 करोड़ की राहत दी गयी। आंध्र प्रदेश - 75 करोड़, बिहार - 38 करोड़, गुजरात - 54 करोड़, जम्मू-कश्मीर - 73 करोड़, कर्नाटक - 17 करोड़, मध्य प्रदेश - 38 करोड़, मणिपुर - 4 करोड़, मिजोरम - 6 करोड़, उड़ीसा - 828 करोड़ ...(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु : यह बता दीजिए कि 721 करोड़ मांग करके पश्चिमी बंगाल

को कितना मिला ? पिछली बार इनके हिस्से का 29 करोड़ देने की बात थी ....**(व्यवधान)** एक पैसा नहीं मिला ...**(व्यवधान)**

श्री रामचन्द्र खूंटिया : 7,900 करोड़ मांगा और आप बोलते हैं 828 करोड़ ...**(व्यवधान)** ड्रॉट में उड़ीसा का नाम नहीं है ...**(व्यवधान)**

SHRI S.VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, let the Minister's reply come first. ...*(Interruptions)*.. After that they can put their questions one by one. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): This is what I am asking them to do. ...*(Interruptions)*..

श्री आर. एस. गवई (महाराष्ट्र) : उड़ीसा को जो आपने 828 करोड़ दिया है वह ड्रॉट में से नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु : एक पैसा नहीं दिया है बंगाल को, 29 करोड़ देने की बात थी ...**(व्यवधान)**

श्री सुंदर लाल पटवा : पहले मेहरबानी करके माननीय सदस्य ..**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) :गवई जी, मंत्री जी को उत्तर तो पूरा कर लेने दीजिए फिर और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए ..:**(व्यवधान)**

श्री आर. एस. गवई : यह कोई ड्रॉट कंडीशन के लिए नहीं दिया। वह दूसरी सिचुएशन के लिए था।

श्री सुंदर लाल पटवा : ड्रॉट का मैं बता रहा हूं सुनें तो ...**(व्यवधान)** राजस्थान- 102 करोड़ ..**(व्यवधान)**

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : एक मिनट। आदरणीय महोदय, यह बताने की कृपा करें कि यह 155 करोड़ जो राजस्थान के लिए राशि आवंटित अभी आपने की है क्या यह सचमुच वहां पर ड्राफ्ट भेज दिया गया है?

श्री सुंदर लाल पटवा : मुझे कुछ सुनने का कष्ट करें तो स्थिति मैं बताता हूं। जो आप जानना चाहते हैं पूरा बताने को मैं तैयार हूं। अगर मेरे कथन में कुछ कमी रह जाए तो फिर प्रश्न करिए, फिर मैं निवेदन करूंगा, आपका समाधान करूंगा। पर मेहरबानी करके, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि मेरी बात सुनने का तो कष्ट करें। अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर मैं क्या करूं।

4.00 P.M

इतनी बेचैनी है। राजस्थान का नाम लेने के लिए मैं तैयार खड़ा हूं आप राजस्थान का सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह प्रश्नोत्तर तो नहीं है। आपके कथन को मैंने पूरा सुना है। मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा, आधा घंटा भी अगर मुझे सुन लें फिर उसके बाद कोई कमी कसर रह जाए तो मुझे आप कठघरे में खड़ा करें। आप जैसे विद्वान से तो ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता हूं **..(व्यवधान)**

श्रीमन, जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है उसमें एक नियमित प्रबंध है जो हमने नहीं किया है। श्रीमान मनमोहन सिंह जी का किया हुआ है, प्रणब मुखर्जी महोदय का किया हुआ है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE(West Bengal): It was not done by me or anybody else. It was done by the Tenth Finance Commission. *...(Interruptions)...* As a Minister, I expect him to know this. *...(Interruptions)...* It was done by the Tenth Finance Commission. *...(Interruptions)...* It was a recommendation given by the Tenth Finance Commission.

SHRI SUNDER LAL PATWA: We are also duty bound. *...(Interruptions)...*

एक माननीय सदस्य : आपके समय का है **..(व्यवधान)**

श्री सुदर लाल पटवा : हम तो अभी आए हैं। जुम्मा-जुम्मा चार दिए हुए हैं। अभी तो हम पालने में झूल रहे हैं **...(व्यवधान)** गिद्धों के श्राप से गायें नहीं मरती हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : गिद्ध ही गायब कर दिए हैं आप लोगों ने **...(व्यवधान)**

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन, जो केंद्रीय आपदा राहत कोष है, जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है उसमें मांग आने के पश्चात केंद्रीय टीम भेजी जाती है । केन्द्रीय टीम अध्ययन करती है और वह सिफारिश करती है कि इतनी असिस्टेंस की आवश्यकता है और यह दी जानी चाहिए । जहां-जहां से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के लिए मांग आई, राजस्थान से आई, गुजरात से आई, मध्य प्रदेश से आई, उन्होंने 1100 करोड़ रुपये का मांगपत्र हमें भेजा । हमने टीम भेजी। कोई भाजपा के नेताओं की टीम नहीं भेजी, एनडीए की टीम नहीं भेजी, बल्कि हमेशा जो जाती है आफीशियल्ज़ की टीम, वही टीम भेजी गई ।

उन्होंने असैस्मेंट करके हमें जो बताया, जो प्रतिवेदन किया, उसमें एक पाई भी कमी किए बगैर, बल्कि कुछ क्षेत्रों में कुछ बढ़ा करके ही राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्रत्येक राज्य को सहायता दी गई । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी मुख्य मंत्री रहा हूं और मैंने भी मांगपत्र भेजा है और जैसा मैंने अनुभव किया वह मैं बताता हूं । जब हम तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो यह समझ करके मांगते हैं कि यदि तोप का लाइसेंस नहीं मिलेगा तो राइफल का तो मिल ही जाएगा, और नहीं तो तमंचे का तो बराबर मिलेगा । निर्णय हम नहीं करते । केन्द्र में बैठ करके हमने निर्णय नहीं किया । उसी प्रकार से टीम भेजी गई जिस प्रकार से माननीय मनमोहन सिंह जी भेजा करते थे । उस टीम ने जो असेस्मेंट करके हमें बताया उसमें हमने कोई कमी नहीं की, कुछ मात्रा बढ़ा करके ही दी है । आज की तारीख में जो राज्य सरकारों के पास संसाधन केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, उनका जिक्र मैं करना चाहूंगा और आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वर्ष 1999-2000 में जो रिलीज़ हुआ वह राजस्थान को 584 करोड़, गुजरात को 383 करोड़, आन्ध्र प्रदेश को 458 करोड़, मध्य प्रदेश को 574 करोड़ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रिलीज़ हुआ, जिसमें सीआरएफ सैन्ट्रल शेयर है आपदा राहत कोष का, ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, एम्प्लायमेंट जेनरेशन के लिए है, ड्रॉट प्रोन एरिया की स्कीम के लिए है, एनीमल हसबैंड्री के लिए है । कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, दोनों मंत्रालयों के विभाग मेरे पास हैं । मार्च के अंतिम सप्ताह में और अभी तक जो राशि विमुक्त की गई है, उसमें से आज जो विभिन्न राज्यों के पास मौजूद है, वह राजस्थान के पास 560 करोड़ रुपये है, गुजरात के पास 377 करोड़ रुपये है, आन्ध्र के पास 138 करोड़ रुपये है, मध्य प्रदेश के पास 99 करोड़ रुपये है । मध्य प्रदेश का कल जरा ज्यादा ही जिक्र हुआ था, हमारे माननीय सदस्य बैरागी जी सदन में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश की कुल स्थिति का विवरण मैं बताऊं, श्रीमन्, उनको टोटल एलोकेशन जो था, उनकी जो एनटाइटलमेंट थी वह 824 करोड़ 82 लाख रुपये की थी और जो रिलीज़ किया गया वह 877 करोड़ 48 लाख रुपया था, 106 प्रतिशत राशि मध्य प्रदेश को रिलीज़ हुई । .....(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : क्या खाली सूखे में ?

श्री सुंदर लाल पटवा : मैंने टोटल बताया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : यह अल्पकालिक चर्चा सूखे और अकाल के ऊपर है । सूखे और अकाल में इस राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के जरिए कितना पैसा दिया गया यह बताइये, बाकी पूरा जोड़ कर मत बताएं ।

श्री अहमद पटेल : राहत कोष से कितना दिया ?

श्री सुंदर लाल पटवा : राहत कोष से जो दिया है वह मैंने अभी बताया है । फिर भी आप कहें तो मैं दोबारा पढ़ दूं ।....**(व्यवधान)**

श्री बालकवि बैरागी : उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी को यह बतलाइए कि कल की बहस केवल सूखे पर आधारित थी। इन्हें बहुत मुश्किल से याद रहता है ।

श्री सुंदर लाल पटवा : धन्यवाद ।

श्री बालकवि बैरागी : मैं इन्हें बहुत करीब से जानता हूं । आप जिस बहस का उत्तर दे रहे हैं, वह सूखे पर थी ।

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन्, सूखे के लिए दोनों राहत कोषों से धन प्रदान किया जाता है । उस के साथ-साथ रोजगार-मूलक योजनाएं, पेयजल की योजनाएं - ये भी सूखे के लिए ही उपयोग में लायी जाती हैं ।

श्री नीलोत्पल बसु : सर, मंत्री जी जो बोल रहे हैं, वह हाउस को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं । वह जिस पैसे के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वह तमाम सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के तहत है and this money the States have to receive, in any case, irrespective of whether it is for drought or floods.

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन् मैंने अलग-अलग दोनों प्रकार का जिक्र किया है । सूखा राहत के अंतर्गत आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष - इन दोनों का मैं ने अलग जिक्र कर के बताया है । इस के अलावा अभी और विशेष उपाय किए हैं । ....**(व्यवधान)**.... इस के अलावा भी सूखे की विपत्ति से लड़ने के लिए तात्कालिक उपाय किए गए हैं । श्रीमन् 20 किलो प्रति परिवार अनाज, जहां चावल का उपभोग होता है वहां चावल और जहां गेहूं का उपभोग होता है वहां गेहूं और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दो किलो अनाज काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत दिया जाएगा । यह कल जारी किया गया है । इस में राजस्थान ने 5 लाख टन मांगा और उसे 5 लाख टन जारी किया जा चुका है । यह कल की सर्वदलीय समिति की बैठक में माननीय खाद्य मंत्री जी ने बताया है । श्रीमन् इन सब योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आज की तारीख में जो पैसा राज्यों के पास उपलब्ध है, उस का मैं ने जिक्र किया है । ....**(व्यवधान)**.... मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बाद में सवाल कर लीजिएगा । श्रीमन् इन सब समस्याओं का निवारण करने के लिए किसी भी प्रकार से जो हमारे वश में है, केन्द्र के वश में है और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, उस से और आगे बढ़कर माननीय प्रधान मंत्री जी ने कल देश को आश्वस्त

किया है, संबंधित राज्यों को आश्वस्त किया है कि सहायता में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, अनाज की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी और पशुओं के लिए भी भूसा और घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा । इस मानव त्रासदी को कम करने के लिए, पशुओं की त्रासदी को कम करने के लिए हम सब मिलकर, जूझकर प्रयास करेंगे इस के लिए उन्होंने आह्वान किया है । मैं सोचता हूं कि इस आह्वान का हम सब स्वागत करेंगे और इस संकट का सामना करने के लिए हम सब संलग्न होंगे । इस के बाद भी अगर ...**(व्यवधान)**....

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए कुछ नीति अपनाई है । क्या उस में बंगाल को कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा ? बंगाल के बारे में कुछ नीति है कि नहीं ? बंगाल ने बाढ़ से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से 721 करोड़ रुपए मांगे थे और केन्द्र सरकार ने 29 करोड़ सेंक्शन किया, लेकिन एक पैसा भी अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन् पश्चिमी बंगाल को जो टीम भेजी गयी थी और उस ने जो रिकमंडेशन की, वह पूरी 29 करोड़ 52 लाख की राशि पश्चिमी बंगाल को दी गयी है । ....**(व्यवधान)**..... श्रीमन् मैं ने जो विवरण बताया है वह राशि 31 मार्च, 2000 को रिलीज कर राज्यों को पहुंचा दी गयी है ।

श्री रामचन्द्र खूंटिया : सर, मिनिस्टर साहब ने जो रिप्लाय दिया है, उसमें उन्होंने उड़ीसा के अफेक्टेड एरियाज़ के बारे में कुछ नहीं बोला है और उड़ीसा को ड्रॉट से निपटने के लिए क्या दिया है, इस बारे में कुछ इनफॉर्मेशन नहीं दी है । सर, इस के अलावा 20 तारीख को एक प्रश्न के उत्तर में मिनिस्टर साहब ने जो लिस्ट दी है, उस में आंध्रप्रदेश का जिक्र है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का जिक्र है, मगर उड़ीसा का जिक्र बिल्कुल नहीं है । उड़ीसा का बहुत एरिया अफेक्टिड है, 18 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टिड हैं ड्रॉट से लेकिन उड़ीसा का कोई ज़िक्र नहीं है, ड्रॉट के लिए कितना पैसा दिया, इसका भी कोई ज़िक्र नहीं है ।

श्री राजू परमार : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने ड्रॉट से निबटने के लिए आपसे कितनी धनराशि मांगी है और मिनिस्ट्री की जो टीम गुजरात में गई, उन्होंने कितना रिकमेंड किया ?

श्री आर.एस. गवई : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना

चाहता हूं कि जो निधि का वितरण हुआ उसके लिए कोई निर्देश निर्धारित किए गए थे Or, is the Government depending only on the Central Teams to go to these States? What is the duty of the Government?

दूसरे, प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि जिस इलाके में सूखा है वहां केवल समिति ही नहीं बल्कि हमारे मंत्री भी पहुंचेंगे, जानकारी लेंगे कि सैंट्रल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की हैं, क्या उसके अलावा भी कोई आवश्यकता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी ने इस दरम्यान किस-किस स्टेट में विज़िट किया और उनकी जो ऑब्ज़रवेशन है वह ऑब्ज़रवेशन क्या जो सैंट्रल कमेटी यहां से गई थी, उससे मेल खाती है?

तीसरे, जो फिगर दिखाई पड़ती है, मैं कोई ऐलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है - मध्य प्रदेश के लिए कम है, आन्ध्र प्रदेश के लिए कम है, उड़ीसा के लिए कुछ भी नहीं है - तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है ?

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री प्रमोद महाजन जी ने एनाउंस किया था कि रेलगाड़ी में पानी भरकर हम सूखाग्रस्त क्षेत्र में भेजेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पानी से भरकर रेलगाड़ी भेजी जाने वाली थी, वह अभी तक चली या नहीं, उसकी क्या व्यवस्था हुई और उस रेल के द्वारा किन-किन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया और कितनी मात्रा में पानी गया और राजस्थान और गुजरात को कितने पानी की जरूरत है ?

दूसरे, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि आज देश में जितने बड़े घराने हैं, बिग हाउसिस हैं, जो पूरे देश को कीमती पानी पिलाते हैं, अच्छे-अच्छे गिलासों में सजाकर मिनरल वाटर पिलाते हैं और बड़े-बड़े लोगों को पानी पिलाते हैं, क्या आपने कभी उन लोगों से भी कहा कि अकाल और सूखे से ग्रस्त जो लोग हैं, जो पानी के लिए छटपटा रहे हैं, उनको पानी पिलाने का कुछ इंतजाम किया जाए और यह मिनरल वाटर वाले बड़े घराने उनको पानी पिलाने का कोई इंतजाम कर रहे हैं या नहीं ? समाज सेवी संस्थाओं से आपने आह्वान किया, प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया, क्या मिनरल वाटर घरानों ने भी आपको कोई सहयोग देने का वायदा किया या वे केवल पैसे लेकर ही लोगों को पानी पिलाते हैं ? उनका इस सामाजिक दायित्व निभाने में कोई हिस्सा है या नहीं ?

श्री बालकवि बैरागी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं । एक तो जिन-जिन सूखाग्रस्त क्षेत्रों, राज्यों का मंत्री जी ने यहां

ज़िक्र किया, हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर में ज़िक्र किया, उन राज्यों में मंत्री जी स्वयं इस संदर्भ में कोई दौरा करने का कार्यक्रम बना रहे हैं ? बना रहे हैं तो राज्यवार बताएं कि वे कब जा रहे हैं ? डेढ़-दो महीने तक तो यह संकट भयंकर रहने वाला है, फिर बरसातें आने की संभावना है, तो क्या उसके पहले आप कोई दौरा इन राज्यों में बनाकर मॉनिटरिंग अपनी आंखों से देखना चाहेंगे ?

दूसरे, आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा की है, तो फाइनेंस कमीशन से या फाइनेंस कमीशन के सूत्रों से आपके अपने विभाग ने इस काम के लिए कब-कब कितना पैसा मांगा क्या इसका कोई ब्यौरा आप दे सकेंगे ।

तीसरे, जैसा कि श्री गवई साहब ने स्वयं प्रश्न किया है, आप स्वयं मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में आपके अपने मन में जो अभी तक करुणा और ममता नहीं जागी है उसके क्या कारण हैं ? वहां के लोगों को उतना सब कुछ क्यों नहीं दिया जा रहा है जोकि आप सर्वत्र देने की बात कर रहे हैं ?

इन तीन बातों पर यदि आप कुछ समाधानकारक बात कह सकेंगे तो हम आपका बड़ा आभार मानेंगे ।

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO (Andhra Pradesh): So far as Andhra Pradesh is concerned, acute famine conditions are prevailing there. We had requested for Rs.750 crores, but they were pleased to grant only Rs.75 crores. I request that the amount may please be enhanced so that we may implement the programme. The hon Minister was saying that we are not able to implement the programme. If they can provide us the wherewithal, we will implement the programme. Then there will be no problem.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की जो विषम परिस्थिति है, उसको देखते हुए माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है । जो आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार को देनी चाहिए, वह पर्याप्त नहीं है । आज राजस्थान में करीब 4 लाख मजदूर कार्य कर रहे हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 करोड़ रुपया दिया है, वह एक महीने की राशि दी है जब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतने समय से वहां भयंकर अकाल की स्थिति है और यह मई, जून में भी जारी रहेगी । तो करीब 6 महीने तक वहां अकाल की स्थिति रहेगी । महोदय, राजस्थान का तापमान भी 45 डिग्री तक पहुंच गया है । इस तरह से भयंकर गर्मी वहां पड़ रही है । पीने के पानी के अभाव के कारण, मनुष्यों के लिए अनाज और पशुओं के लिए चारे के अभाव के कारण वहां बड़ी

परेशानी हो रही है । तापमान दिनों-दिन बढ़ रहा है जिसके कारण पीने के पानी की समस्या, पशुओं के लिए चारे की समस्या और मनुष्यों के लिए अनाज की समस्या बढ़ती जा रही है । इससे मौसमी बीमारियां फैलने का भी डर है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए कुछ ऐक्स्ट्रा राशि दी है ? यदि दी है तो वे बताएं कि हमने लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए इतनी राशि दी है ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, the first quarter of the Calamity Relief Fund has already been dispatched to all the States. As far as the second quarter is concerned, the Central Government has dispatched it to only two States. Nearly eleven States have been identified as the drought-hit areas. That is why I want to know whether the Government of India has decided to release the second quarter of the Calamity Relief Fund at least to those States which have been identified as drought affected areas. Secondly, we are told that the Reserve Bank of India has given some instructions to the nationalized banks to mitigate the sufferings of the farmers. If so, what are the real instructions provided by the Reserve Bank of India to the nationalized banks in regard to the principal amount and the interest amount of the medium and long-term loans. Thirdly, I would like to know whether the Government is giving the additional quantity of rice to the States for supply not only to those who are below the poverty-line, but also to those who are above the poverty line.

श्री राजीव शुक्ला (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि जो टैंपरेरी रिलीफ है, सिर्फ उसी की बात हो रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि 1991 के बाद इन 8-9 सालों में कोई सूखा नहीं पड़ा । कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि यह साल-साल का रोना बंद हो क्योंकि एक साल इंतजाम होता है, फिर आगे व्यवस्था नहीं होती । आज एक आर्टिकल छपा है एक ऐनवायरमेंटलिस्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के वॉटर रिज़र्व बनाए जाएं तो हर साल इतना पानी जमा हो सकता है और कभी भी सूखा पड़े तो उसका मुकाबला किया जा सकता है । अगर माननीय मंत्री जी यह बताएं कि वे भविष्य में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या परमानेंट अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा ।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Sir, the people are coming on a large-scale for the relief work. I would like to know whether the Government is supposed to give water to those who are coming at the work

site or not. There are reports that in some areas where water was given to the workers at the work they were asked to pay for it.

Secondly, I would like to know whether the Government is supposed to arrange centers for the one-year or two-year children accompanying the women coming for the relief work. I would like to know whether the Government is supposed to make such an arrangement or not as per the directions and instructions of the Central Government.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): There is a shortfall in the rainfall. As a result of this, crops have failed. May I know from the hon. Minister whether the Government is thinking of giving a set-off to those agriculturists who have taken loans for agricultural purposes? This is one thing. Secondly, there is the agricultural crop insurance scheme which was taken up by the co-operative sector for which premia for the month of May, June and July were accepted by the insurance companies. The last instalment for the month of August which was sent in the month of September was returned by the General Insurance Corporation. For about three months, cheques were returned to almost all the district co-operative banks in the State of Gujarat. I would like to know whether any consideration has been given to indemnify the agriculturists who were insured.

श्री सुन्दर लाल पटवा : श्रीमन्, उड़ीसा का जिक्र आया कि सूखा राहत के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया। उड़ीसा राज्य से सूखा राहत के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। कल उड़ीसा के मुख्य मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है और आवश्यकता होगी तथा वह आग्रह करेंगे तो उसका प्रबंध करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने ढाई लाख घरों की आवश्यकता बताई थी। हमने 50 हजार घर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जारी कर दिए थे। उन्होंने 50 हजार घरों के आबंटन करने का प्रबंध कर लिया है। कल उन्होंने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दो लाख आवासों की मांग की। उनका भी प्रबंध करने के लिए मैंने कल शाम को आदेश दिया। जहां तक गुजरात की मांग का सवाल है, मैंने बताया कि उनकी मांग 700 करोड़ रुपए की थी। वहां टीम भेजी गई। टीम ने क्या प्रतिवेदन किया इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है। परन्तु एक आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं कि टीम ने जो प्रतिवेदित किया उसमें एक पाई भी कम करने की हमने कोशिश नहीं की, उसमें कुछ बढ़ा करके किया है कहीं-कहीं। उसका विवरण अभी मेरे पास नहीं है।

श्री राजू परमार : वही हम जानना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : वह बता रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आम तौर पर टीम के प्रतिवेदन को सार्वजनिक नहीं किया जाता। आपको अगर जानकारी चाहिए तो पत्र लिखिए मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

मंत्री के दौरे का जिक्र किया गया है। बैरागी जी ने भी हमको उकसाया है कि आप कब जाने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं। राजस्थान और गुजरात का दौरा मैने बनाया था। मै 24 और 27 तारीख को वहां जाने वाला था। 24 तारीख को लोक सभा में यह बहस लग गई इसलिए मैंने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया है। अब 30 तारीख को मैं गुजरात में स्वयं जाना चाहता हूं। राजस्थान भी जाना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जाकर के वहां कोई और नया निरीक्षण करके कोई नई सूचना ले आएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। जो हमारी निरन्तर प्रक्रिया और व्यवस्थाएं हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। जहां तहसीलदार काम कर सकता है वहां तहसीलदार करे, कलेक्टर कर सकता है वहां कलेक्टर करे, राज्य सरकार कर सकती है तो वहां राज्य सरकार करे। हम राज्य सरकार की बात पर भरोसा नहीं करेंगे और खुद वहां कुछ देखने जाएंगे इसका कोई औचित्य नहीं है? जब मंत्री जाते हैं तो जो अमला राहत कार्यों में लगा है वह मंत्री जी के इर्द-गिर्द घूमने लगता है। जहां तक पानी का संबंध है, पानी कहां गया, कितने लीटर कहां भेजा, कहां-कहां वितरण किया इसकी जानकारी मेरे पास होगी यह तो सोचना भी ठीक नहीं है। परन्तु पानी के लिए रेलें तैयार हैं, चारे के प्रबंध के लिए तैयार हैं। रेल बिना चार्ज -निशुल्क इसको परिवहन करेगा, यह घोषणा की जा चुकी है। जहां से मांग आएगी वहां भेजने के लिए तैयार हैं। ....**(व्यवधान)**....

श्रीमती सरोज दुबे : मैं यह जानना चाहती हूं कि उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है?

श्री सुन्दर लाल पटवा : राज्य सरकारें मांगेंगी तभी तो क्रियान्वयन करेंगे या मैं अपने मन से रेल दौड़ा दूं। ....**(व्यवधान)**....

श्रीमती सरोज दुबे : इतने जोरशोर से बोल रहे हैं कि रेल भर करके पानी जाएगा। अभी तक पानी वहां गया नहीं है। वहां लोग पानी के इंतजार में बैठे हैं। ....**(व्यवधान)**....

श्री सुन्दर लाल पटवा : कहां पहुंचाना है, यह राज्य सरकार कहे। कहां प्रबन्ध करना यह राज्य सरकार कहे। हर काम में केन्द्र दौड़ करके हस्तक्षेप नहीं करता है, यह

आपकी जानकारी में है। जहां तक ....(**व्यवधान**).... मैंने फिर कहा है कि मैं स्वयं मुख्य मंत्रियों से मिलने और स्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां जाने का यथासम्भव प्रयास करूंगा। परन्तु मैं मानता हूं कि वहां की स्थिति के बारे में जो अध्ययन राज्य सरकारों के द्वारा भेजा जा रहा है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

महोदय, आप जानते हैं कि जब हम जाते हैं तो एक वीआईपी अरेंजमेंट होता है। राहत कार्य में लगे हुए बड़े अफसर हमारे आजू-बाजू में घूमने लगते हैं और उस कार्य में बाधा पहुंचती है। फिर भी, मैं वहां जाऊंगा। वित्त प्रबन्ध मध्य प्रदेश में कम किया गया है, मध्य प्रदेश में करुणा कब जागेगी, ऐसा हमारे बैरागी जी का कहना है। मध्य प्रदेश में कहां वित्त की कमी है? ....(**व्यवधान**)....

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में सूखे के बारे में वहां की सरकार चिंतित नहीं है। आज 14 नये मंत्री बना दिए गए हैं। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में सूखे की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर मंत्रिमंडल में मंत्री बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या सरकार को सूखे की चिन्ता है? ऐसे समय में मंत्रिमंडल क्यों बढ़ाया गया है? वहां जनता की चिन्ता के बजाए विधायकों की चिन्ता करके मंत्री पद बांटे जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश में मंत्री बढ़ाये जा रहे हैं। वहां ऐसे सूखे में मंत्रियों की बरसात हो रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार : आप लोग यहां पर एक्सपैंशन मत करना।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि जरा आपकी सलाह ले लें और उसके बाद कुछ करें। ....(**व्यवधान**)....

श्री राजू परमार : मध्य प्रदेश के अपने मित्र को इस बारे में बताइये। ....(**व्यवधान**)....

श्री सुन्दर लाल पटवा : उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक चालू वर्ष 2000-2001 में वित्त सहायता पहुंचाने का प्रश्न है उसमें सभी सहायक योजनाओं के अन्तर्गत हमने प्रथम किश्त बिना किसी औपचारिकता का इंतजार किए हुए जारी कर दी है और यह कहा है कि इस किश्त का यूटिलाइजेशन हो जाए और आप आग्रह करें तो दूसरी किश्त भी हम जारी करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय आपदा कोष में जो पैसा देना था उसमें तीन और एक का रेशो है, 75 प्रतिशत केन्द्र का अंशदान है और 25 प्रतिशत राज्यों का अंशदान है। राज्यों का अंशदान कहीं से भी एक पैसा नहीं आया है और उसका आग्रह भी हमने नहीं किया है। बिना उनके आग्रह के 100 प्रतिशत पैसा केन्द्र द्वारा उन्हें उपलब्ध

उपलब्ध कराया गया है। उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। ब्रह्म कुमार जी ने फिर से आग्रह किया है कि मैं गुजरात की सरकार को ऐसा कहूं कि वहां रोजगार पर लगी हुई महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उचित प्रबन्ध करें। क्या गुजरात की सरकार से आपका वार्तालाप नहीं है? ....**(व्यवधान)**....

श्री राजू परमार : वे बुलाते ही नहीं हैं। वे कभी एमपी की मीटिंग बुलाते ही नहीं हैं। ....**(व्यवधान)**....

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप उनको चिट्ठी भेजें। ....**(व्यवधान)**.... केशुभाई आपके पुराने मित्र हैं। बैरागी जी, से मेरा यह कहना है, अपना कथन समाप्त करने से पहले उन्हें मैं उन्हीं के तरीके से एक निवेदन करना चाहता हूं। यह समय आपस में आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। यह समय मिलकर विपदा का सामना करने का है। प्रधान मंत्री जी ने जो आह्वान किया है, अगर लोग समझें तो वह उन लोगों के लिए भी है जो मिनिरल वॉटर पीते हैं । मेरा भाई बैरागी जी को कहना है ..**(व्यवधान)**..

श्रीमती सरोज दुबे : हैलीकॉप्टर से बोतलें और गिलास जाने चाहिए । गांव में सूखे के कारण पीने के पानी की जरूरत है ।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आपके लिए तो भिजवाने की जरूरत नहीं है । अंत में मेरा बैरागी जी को कहना है कि

तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच ।

हम दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच ।।

हम दोनों उम्रों की सड़क पर इतनी दूर निकल आए हैं ।

देख तो सामने मील का पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच ।।

श्री अहमद पटेल : क्या तुमको पता नहीं है, लहरे आती जाती हैं । ..**(व्यवधान)**.. मैं भी सोचूं, तू भी सोच ।

श्री आर.एस.गवई : सर, मेरा एक बुनियादी सवाल था, एक सप्लीमेंटरी सवाल था । ..**(व्यवधान)**..

श्रीमती सरोज दुबे : हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं । ..**(व्यवधान)**..

श्री आर.एस.गवई : माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया था । मैंने कहा था कि

यह गाइडलाइन्स प्राइम मिनिस्टर ने दी कि माननीय मंत्री जहां-जहां सूखा है, वहां पहुंचें और ऑब्ज़र्वेशन करें । यह ठीक है कि उन्होंने जवाब दिया है कि मंत्री के जाने से कोई फायदा होता है, ऐसा नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए हो गया ।

श्री आर.एस.गवई : नहीं, मेरा इस संबंध में सवाल है। No,no. I want to put a basic question. You know that we have adopted a democratic principle, not a routine one. We respect the bureaucratic approach. They are the advisors. But the final decision lies with the Government. The hon. Minister, Shri Sunder Lal Patwa, is supreme. He may have the advice from the bureaucrats, he may have the advice from the Central Committee, but when he goes to a particular State and makes an on- the- spot study.... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): He has noted down your point.

SHRI R.S.GAVAI: Sir, he is himself denigrating his position by saying that the Tehsildar is correct and the Minister is not empowered to do it. That is my fundamental question. I am safeguarding his interest. He should not roll down the democratic spirit of the Government. Of course, for routine procedure, bureaucrats are there. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The Minister has noted down your points.

Now, clarifications on the statement made by the Minister regarding price policy for copra for 2000 season and jute for 2000-2001 season. Shri Santosh Bagrodia.

CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER

Price Policy for Copra for 2000 season and Raw Jute for 2000-2001 season

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : सर, मैं बिना स्टेटमेंट के सवाल पूछ लेता हूं । मेरा सवाल जूट के बारे में है, खोपरा के बारे में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जूट के बारे में केवल यही कहना चाहता हूं कि जूट का दाम जो आप बढ़ा रहे हैं, वह तो बहुत आवश्यक है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, वह बढ़ने दीजिए, उसमें मुझे